तिब्बत देश

अब दलाई लामा को चीनी विषकन्याओं से खतरा

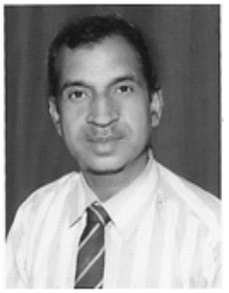

तिब्बत समर्थक भारतीयों के लिए प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 2012 का विष्वप्रसिद्ध टेम्पलटन पुरस्कार परमपावन दलाई लामा जी को प्रदान किया गया है। अनेक अवसरों पर अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से परमपावन जी का अभिनंदन वास्तव में सत्य, अहिंसा, शांति एवं सद्भाव का अभिनंदन है। पुरस्कार में प्राप्त राशि को परमपावन जी ने भारतीय बच्चों के कल्याण तथा विज्ञान पढ़ने वाले तिब्बती भिक्षुओं की मदद के लिए हाथोंहाथ प्रदान कर दिए। इससे टेम्पलटन सम्मान का भी सम्मान हो गया। बधाई हो परमपावन जी।

बधाई के बाद चिंता की बात। हाल ही परमपावन चौदहवें दलाई लामा जी ने स्वयं रहस्योद्घाटन किया है कि चीन की सरकार विषकन्याओं की मदद से उनकी हत्या कराने की साजिश रचे हुए है। प्रशिक्षित विषकन्यायें उन्हें खतक देते समय या उनके दर्शन करते समय उनसे आशीर्वाद लेने के बहाने विष दे सकती हैं। गुपचुप तरीके से। अनेक मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन सरकार दलाई लामा की स्वास्थ्य संबंधी सुचनायें लगातार खुफिया तरीके से जुटा रही है। नए रहस्योद्घाटन के बाद दलाई लामा जी की सुरक्षा और ज्यादा मगबूत करना भारत सरकार का नैतिक एवं कानूनी दायित्व है।

मजे की बात यह कि इस बार भी चीन सरकार ने दलाई लामा द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन को अफवाह बता दिया है। उसने यहाँ तक कह दिया है कि दलाई लामा चीन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं तथा संपूर्ण विश्व में चीन सरकार को बदनाम कर रहे हैं। यह उसी चीन सरकार का स्पष्टीकारण है, जिसने पचास वर्ष पूर्व 1962 में भारत पर हमला कर दिया था और भारत के बड़े भूभाग पर अपना अवैध नियंत्रण कर लिया था। तब से लेकर अब तक चीन सरकार भारत के कई नए क्षेत्रों को हड़पने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाती आ रही है।

भारत सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि "हिन्दी–चीनी भाई–भाई" के खोखले नारे और तथाकथित "पंचशील" के मायाजाल में फिर से फँसने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है कि भारत सरकार इतिहास से जरूरी सबक लेने को तैयार नहीं है।

भारत सरकार के गृहमंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि वह धर्मशाला में रह रहे सत्रहवें कर्मापा ओग्येन ठिनले दोर्जे को कर्मापा कहना बंद कर दे। कैसा विचित्र सुझाव है! नौ सौ साल पुराना है कर्मापा का पद। वर्तमान कर्मापा जी गत बारह वर्षों से भारत में सबके कल्याण हेतु अथक प्रवास एवं धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। उनको परमपावन दलाई लामा जी की पूर्ण मान्यता प्राप्त है। चीन की सरकार स्वयं उन्हें कर्मापा की मान्यता दे चुकी है। ऐसे में चीन के साथ कथित मित्रता के नाम पर कर्मापा संबंधी भारत सरकार का सुझाव भारतीय पंथनिरपेक्षता की भावना के भी प्रतिकूल है।

चीन सरकार भारत को चारों ओर से घेरने में लगी है। चीन का भारत विरोधी सहयोग पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यांमार, श्रीलंका, फिलिपींस तथा मालद्वीप के साथ है। वह नेपाल में भारत के सिर तक सड़कें और रेलमार्ग बनाने में लगा है। पाकिस्तान में सड़कें बना रहा है। भारत के पड़ोस में उसने नौसैनिक अड्डे बना लिए हैं और हवाई पदि्टयाँ निर्मित कर ली हैं।

ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने एक ही विकल्प है कि वह तिब्बत की आजादी के संघर्ष में सहयोग करे। तभी भारत एवं चीन के बीच तिब्बत एक मध्यस्थ राज्य (बफर स्टेट) पूर्व की भाँति बन सकेगा। इसीसे भारत–चीन संबंध मधुर हो सकेंगे तथा एशिया में शांति बहाल हो सकेगी।

प्रो. श्यामनाथ मिश्र

पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राज.)

तीर्थयात्रा से लौट रहे तिब्बतियों को चीन ने हिरासत में लिया

इस दोस्त को संकेतों में मिले संदेशों से यह भी संकेत मिला है कि मां को हिरासत में लेकर एक गेस्टहाउस में पूछताछ के लिए रखा गया और उन्हें ठहरने के लिए हुए खर्चों का भी भुगतान करना पड़ा।

(न्यूयॉर्क टाइम्स, 7 अप्रैल, धर्मशाला)

इस साल जनवरी में भारत में हुए एक महत्वपूर्ण बौद्ध समागम से वापस तिब्बत लौट रहे सैकड़ों तिब्बतियों को चीनी सुरक्षा अधिकारियों ने बिना किसी आरोप के गिरफ्तार कर लिया है। इन तिब्बतियों के भारत में निर्वासन में रह रहे रिश्तेदारों, दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और निर्वासित तिब्बती सरकार के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीनी अधिकारियों ने तीर्थयात्रा से लौट रहे तिब्बतियों को इतनी बड़ी संख्या में हिरासत में लिया है। इस तरह का बौद्ध समागम हर साल भारत के अलग–अलग जगहों पर आयोजित किया जाता है। इनमें से बहुत से तीर्थयात्री बुजुर्ग हैं और उन्हें मध्य तिब्बत (तथाकथित तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र) में दो माह से ज्यादा समय से हिरासत में रखा गया है। हिरासत में लोगों पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इन तिब्बतियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें जबरन देशभक्तिपूर्ण शिक्षा दी जा रही है तथा यह भी आदेश दिया गया है कि वे दलाई लामा की निंदा करें। दलाई लामा ने ही कालचक्र नाम के इस बौद्ध समागम की अध्यक्षता की थी। हिरासत में लिए गए लोगों को होटलों, स्कूलों, सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों या सैन्य चौकियों में रखा गया है और उन्हें भोजन एवं ठहरने का खर्च भी देने को मजबूर किया गया है। इस तरह की हिरासत से ऐसे समय में चीन सरकार के प्रति तिब्बतियों में असंतोष और बढ़ने की आशंका है जब समूचे हिमालयी पठार में तनाव हाल के वर्षों में चरम पर पहुंच गया है।

इन तीर्थयात्रियों को नेपाल के रास्ते सड़क मार्ग से लौटते समय सीमा चौकियों पर या हवाई मार्ग से आने वालों को तिब्बत की राजधानी ल्हासा में गिरफ्तार किया गया। अध्ययन करने वालों ने बताया कि कई लोगों को रिहा भी किया गया है और जो लोग आधिकारिक रूप से किसी और क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें अपने मूल इलाकों में जाने का आदेश दिया गया है।

इन अनुसंधानकर्ताओं ने रिहा हुए तीर्थयात्रियों और उनके दोस्तों एवं रिश्तेदारों से बात कर यह सब जानकारी ली है। कालचक्र समारोह, तिब्बती बौद्धों का एक महत्वपूर्ण उपदेश परंपरा है और इसका आयोजन जाड़े के दिनों में बोधगया में हुआ था। बोधगया भारत के बिहार राज्य में स्थित वही जगह है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दलाई लामा धार्मिक उपदेश देने के लिए हिमालयी पहाड़ी शहर धर्मशाला के अपने निवास से वहां गए थे और तिब्बतियों के साथ ही दुनिया भर के बौद्ध इस समागम में शामिल हुए। वैसे तो चीन सरकार दलाई लामा की आलोचना करती रहती है और उन्हें 'अलगाववादी' बताती है,लेकिन इस समागम के धार्मिक महत्व को देखते हुए कई अधिकारियों ने चुपचाप तिब्बतियों को भारत जाने की इजाजत दे दी थी।

इस साल चीनी अधिकारियों ने इस समारोह में शामिल होने के इच्छुक कई भिक्षुओं को पासपोर्ट नहीं दिया, कुछ अन्य इलाकों के लोगों को ढील दी गई और यून्नान प्रांत के तिब्बतियों को पहली बार इस समारोह में शामिल होने की मंजूरी दी गई। इस समागम में शामिल होने के लिए बहुत से तिब्बती अक्सर चीनी पासपोर्ट पर नेपाल के रास्ते भारत पहुंचते हैं या सीधे हवाई मार्ग से भारत पहुंच जाते हैं और वे चीनी अधिकारियों को इस बात की भनक नहीं लगने देते हैं कि वे कालचक्र समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। निर्वासित तिब्बती सरकार का अनुमान है कि इस साल चीन के तिब्बती इलाकों से करीब 8,000 तिब्बती कालचक्र समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। यह बात साफ नहीं हो पा रही है कि जब वापसी पर गिरफ्तार ही करना था तो चीनी अधिकारियों ने इतनी बड़ी संख्या में तिब्बती तीर्थयात्रियों को इस बार कालचक्र में शामिल होने के लिए देश से बाहर जाने की इजाजत क्यों दी। यह उत्पीड़न तिब्बती इलाकों में बढते टकराव का ही हिस्सा लगता है जिसमें साल 2008 की जनक्रांति के बाद पिछले साल सबसे ज्यादा तीव्र और लगातार विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात आत्मदाह की लहर हैः चीनी शासन के विरोध में कम से कम 32 लोग खुद को आग लगा चुके हैं जिनमें से करीब दो दर्जन लोगों की मौत हो गई है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि आत्मदाह करने वाले कुछ लोगों को दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और वे दलाई लामा के निर्देश पर काम कर रहे थे। जबकि दलाई लामा ने ऐसी घटनाओं में किसी तरह शामिल होने की बात सिरे से खारिज की है। निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे ने कहा, "मैंने सुना है कि तीर्थयात्रा से लौटने वालों को हिरासत में ले लिया गया है और कई को होटलों के कमरों में रखा गया है। उनसे नियमित रूप से पूछताछ की जा रही है। उनसे यह पूछा जाता है कि निर्वासित तिब्बत सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री, अन्य अधिकारी, दलाई लामा और पूर्व प्रधानमंत्री सामदोंग रिनपोछे ने कालचक्र के दौरान क्या भाषण दिया था। मानवाधिकार संगठनों और तिब्बत के लिए आवाज़ उठाने वाले संगठनों ने कई साक्षात्कार के माध्यम से हासिल जानकारियों के आधार पर रिपोर्ट तैयार किए हैं। ह्यूमन राइट्स वाच ने एक बयान में कहा, "सत्तर के दशक के अंतिम सालों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि तिब्बत में चीनी प्रशासन ने इतने बड़े पैमाने पर आम व्यक्तियों को हिरासत में लेकर उन्हें 'पुनर्शिक्षा

कक्षाओं' में जाने को मजबूर किया है। संगठन ने कहा कि यह साफ नहीं हो पाया है कि हिरासत में लिए गए लोगों को कब तक बंद रखा जाएगा और इस बात की भी कोई खबर नहीं है कि काचलक्र समारोह से लौट रहे चीन के प्रभावी नस्लीय समूह हान समुदाय के 700 लोगों में से किसी को गिरफ्तार किया गया हो। तिब्बत की नीति की निगरानी करने और तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र के सीमा संबंधी मसले पर मदद करने वाले यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट के बीजिंग कार्यालय में हमने शुक्रवार को कई फोन कॉल किए लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिला। चीन में अंग्रेजी के सरकारी समाचार पत्र 'चाइना डेली' में 28 मार्च को छपी टिप्पणी से इस बात पर रोशनी पड़ती है कि कालचक्र के बारे में वहां के कट्टरपंथी क्या सोचते हैं। बीजिंग स्थित चाइना तिब्बतोलॉजी रिसर्च सेंटर में सहायक अनुसंधानकर्ता जियो जी द्वारा लिखित इस टिप्पणी में कहा गया है कि इस साल का काचलक्र, "सिर्फ राजनीतिक जमावड़ा नहीं बल्कि दलाई लामा एवं उनके गुट द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के नाम पर आयोजित एक राजनीतिक तमाशा था। इस सभा के दौरान घृणा, आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले उपदेश दिए गए। स्वयंभू 'तिब्बत की निर्वासित सरकार' ने गैरजिम्मेदाराना तरीके से यह घोषणा की कि वह आत्मदाह कर आत्महत्या करने वाले तिब्बती जनता की भावना की सराहना करती है।"मंगलवार को अमेरिकी सरकार के आर्थिक सहयोग से चलने वाली रेडियो फ्री एशिया ने खबर दी कि ल्हासा में हिरासत में रखे गए बहुत से लोग इसी दिन रिहा किए गए हैं, लेकिन ल्हासा के बाहर ल्होका में बंदी बना कर रखे गए कम से कम 200 लोगों को अब भी नहीं छोड़ा गया है। धर्मशाला में रहने वाली एक तिब्बती महिला ने एक इंटरव्यू में बताया कि कालचक्र में शामिल होने वाले उसके एक रिश्तेदार को ल्हासा में उसके परिवार के सदस्यों ने बताया कि अधिकारी यह चाहते हैं सभी तीर्थयात्री लोसार से पहले घर वापस आ जाएं। लोसार तिब्बती नव वर्ष है जो फरवरी के अंत में पड़ता है। महिला का वह रिश्तेदार तुरंत ल्हासा लौट गया, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। निर्वासित सरकार के पूर्व कर्मचारी और लेखक भुचुंग सोनम ने बताया कि धर्मशाला में रहने वाले उसके एक दोस्त को पता चला है कि हिरासत में लिए गए लोगों में उनकी मां भी शामिल हैं। उनके दोस्त ने ल्हासा में अपनी बहन को फोन कर यह पता लगाने को कहा है कि मां की हालत कैसी है। भुचुंग के अनुसार दोस्त की बहन ने बताया, "मां को जुकाम है और वह घर वापस आने से पहले कुछ दिन अस्पताल में भरती रही है, हालांकि वह घर सिर्फ लोसार के लिए ही आ पाई है और उसे फिर से अस्पताल में वापस जाना होगा जहां उसे और इंजेक्शन दिए जाएंगे।" इस दोस्त को संकेतों में मिले संदेशों से यह भी संकेत मिला है कि मां को हिरासत में लेकर एक गेस्टहाउस में पूछताछ के लिए रखा गया और उन्हें ठहरने के लिए हुए खर्चों का भी भुगतान करना पड़ा। भुचंग सोनम ने बताया कि दोस्त की मां को सिर्फ लोसार के लिए रिहा किया गया है, लेकिन उनसे और पूछताछ के लिए बाद में वापस लौटने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत से तीर्थयात्रा करके बड़े पैमाने पर लौट रहे लोगों को हिरासत में लेने का बीजिंग का निर्णय दलाई गुट के प्रभाव को लेकर उसका पीड़ोन्माद ही है।"

बाबाओ एक हटटा–कट्ठा मजदूर है।

तेनपा दार्गे की मौत, कीर्ति मठ पर सैनिकों का कब्जा

(तिब्बत डॉट नेट, 9 अप्रैल)

चीन सरकार के दमन के विरोध में आत्मदाह कर लेने वाले कीर्ति मठ के भिक्षु तेनपा दार्गे की 7 अप्रैल को मौत हो गई। गौरतलब है कि तेनपा दार्गे और छेमी पालदेन ने 30 मार्च, 2012 को आत्मदाह कर लिया था। ये दोनों भिक्षु पूर्वी तिब्बत के सोदुन कीर्ति मठ से जुड़े थे। छेमी पालदेन की आत्मदाह के अगले दिन ही मौत हो गई थी, जबकि तेनपा दार्गे गंभीर रूप से बीमार थे। दार्गे की नाबा इलाके के एक अस्पताल में 7 अप्रैल को सुबह 9.23 बजे मौत हो गई। उनके शव का चीनी अधिकारियों ने अस्पताल में ही करीब एक बजे अंतिम संस्कार कर दिया। उसी दिन सायं 4 बजे उनके रिश्तेदारों को उनका अवशेष सौंप दिया गया। ऐसी भी खबर मिली है कि जब तेनपा दार्गे के अवशेष को सोदुन कीर्ति मठ ले जाया जा रहा था तो सेना की तीन बड़ी टुकड़ियां स्थानीय जनता पर कड़ी नजर रखे हुई थीं। कीर्ति मठ और उसके आसपास के इलाकों में अब भी सेना की भारी मौजूदगी बनी हुई है।

तिब्बत से आने वाली खबरों के अनुसार तिब्बत के उत्तर–पूर्वी नाबा इलाके में स्थित जामथांग में दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है।

ड्राकगो में दमन जारी, कई लोगों को कारावास की सजा

(तिब्बत डॉट नेट, 30 अप्रैल, धर्मशाला)

खाम ड्राकगो में चीनी शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही इस इलाके में चीनी सैनिकों की कठोर और दमनकारी मौजूदगी जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई भिक्षुओं को मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें अलग–अलग अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई है। सोनम धारग्याल ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। उन्हें 10 साल तक कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य तिब्बती पेमा वूएसल को 5 साल तक कारावास की सजा सुनाई गई है। पांच अन्य व्यक्तियों

क्विंघई चीन का तीसरा सबसे गरीब प्रांत है।

को भी 23 जनवरी को खाम ड्राकगो में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के लिए विभिन्न अवधि के कारवास की सजा सुनाई गई है। तिब्बत से आने वाली नवीनतम खबरों से यह भी पता चलता है कि 26 अप्रैल को अन्य 16 तिब्बतियों को विभिन्न अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। वांगछेन सेरिंग (आयु 30 साल) को 9 साल के कारावास, जबकि छोनम (आयु 25 साल), अजी शोपो (आयु 50 साल), झिपे (आयु 30 साल), कुंथो (आयु 20 साल), खुंदुप (आयु 30 साल), नेनडक (आयु 30 साल से ऊपर), फुरपा सेरिंग (आयु 30 साल से ऊपर), और वांगत्से (आयु 20 साल से ऊपर) को 2 से 13 साल की सजा सुनाई गई है। एक अन्य व्यक्ति सोनम ल्हुनडुप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कारावास की सजा पाने वाले सभी 16 तिब्बतियों का पूरा विवरण पता नहीं हो पाया है।

नाबा में दो युवा तिब्बतियों ने आत्मदाह किया

"यदि बड़े पैमाने पर लोगों को बसाने की यह योजना कारगर हुई तो यह स्थानीय तिब्बतियों के परंपरागत संस्कृति पर इसका व्यापक असर होगा।"

(तिब्बत डॉट नेट, 20 अप्रैल, धर्मशाला)

तिब्बत से आने वाली खबरों के अनुसार तिब्बत के उत्तर–पूर्वी नाबा इलाके में स्थित जामथांग में दो और तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। नोमैड परिवारों से जुड़े करीब 20 साल के छोपेक क्याग और सोनम ने जामथांग के जोनांग गोछेन मठ के पास स्थित बर्मा टाउनशिप में स्थित सरकारी कार्यालय के पास अपने शरीर में आग लगा ली। आत्मदाह के बाद इन दोनों की मौत हो जाने की खबरें हैं। इसके बाद इन दोनों तिब्बती नागरिकों के शव को अर्द्धसैनिक बलों के जवान अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे लेकिन स्थानीय तिब्बतियों के विरोध की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए। स्थानीय लोग प्रार्थनाएं करने के लिए शवों को मठ के अंदर ले गए। इसके बाद इस इलाके में बड़ी संख्या में सेना की तैनाती कर दी गई जिससे तनाव काफी बढ़ गया है।इसके पहले इस साल 19 फरवरी को नांगड्रोल नाम का 18 साल का एक तिब्बती युवक जामथांग में ही आत्मदाह कर शहीद हो गया था। तिब्बती संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए सक्रिय नांगड्रोल ने अन्य तिब्बती नागरिकों से आह्वान किया था कि वे अपनी भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान की रक्षा के लिए एक हो जाएं। इस साल 26 जनवरी को 20 साल के एक अन्य तिब्बती नागरिक ओग्येन की गोली लगने से मौत हो गई थी, जब थारपा को हिरासत में लेने का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। थारपा नांगड्रोल का सहपाठी था और उसे ऐसे पत्रक वितरित करते हुए गिरफ्तार किया गया था जिसमें कहा गया था कि आत्मदाह आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को तिब्बत में वापस लाने का आह्वान हैं। उसने कहा था कि आत्मदाह तब तक जारी रहेंगे जब तक चीनी प्रशासन इन मांगों को पूरा नहीं करता। मार्च, 2009 से तिब्बत में अब तक आज़ादी और परमपावन दलाई लामा को उनकी मातृभूमि में वापस लाने की मांग को लेकर 35 तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं।

चीन सरकार के जमीन हड़पने के खिलाफ दो साल से संघर्ष कर रहे भूकंप पीड़ित तिब्बती

(रायटर्स, गेगु, 26 अप्रैल)

चीन के उत्तर–पश्चिम क्विंघई प्रांत में आए प्रलयकारी भूकंप के बाद पिछले दो साल से तिब्बती समुदाय के बाओबाओ और 29 अन्य बेघर लोग उनकी जमीन हड़पने के विरोध में कई सरकारी इमारतों के बाहर धरना दे रहे हैं। लेकिन 41 साल के बाओबाओ ने बताया कि गेगु (चीनी में युशु) का कोई भी अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। बाबाओ एक हटटा–कट्ठा मजदूर है। उसने बताया कि सरकारी अधिकारी करीब 600 लोगों (जिसमें ज्यादातर तिब्बती हैं) को जबरन दूसरी जगहों पर बसाने की धमकी दे रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक उनकी जमीन प्रमुख रियल एस्टेट का हिस्सा है और यहां पर 'पारिस्थितिकी पर्यटन केंद्र' बनाया जाएगा। सरकार के इस कदम से काफी असंतोष है क्योंकि चीन के दो महत्वपूर्ण ज्वलंत सामाजिक समस्याओं (जमीन हड़पने और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ दुर्व्यवहार) के इस संगम से तनाव बढ़ रहा है और इससे इलाके में सामाजिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है। बाओबाओ ने बताया कि इस जमीन अधिग्रहण से अधिकारियों के घरों को बख्श दिया गया है। अपने मकान के सामने ही एक टेंट में जीवन गुजार रहे बाओबाओ ने रायटर्स को बताया, "हम यह बात नहीं समझ पा रहे कि आखिर अधिकारियों के मकानों को क्यो छोड़ दिया गया और आम आदमी के घरों को हड़प लिया गया। वे दोहरी नीतियां अपना रहे हैं: अधिकारियों के लिए अलग और आम जनता के लिए अलग। गौरतलब है कि समूचे चीन में जमीन विवाद काफी आम हैं, लेकिन तिब्बती बहुल इलाकों में यह काफी बढ़ गए हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और बहुसंख्यक हान चीनियों से नाराज तिब्बती सबसे असंतोषग्रस्त अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं। मार्च, 2011 से अब तक चीनी शासन के विरोध में 34 तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। ज्यादातर तिब्बती चीन के कथित तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वे बड़ी संख्या में क्विंघई,सिचुआन, गांसू और यून्नान के पड़ोसी प्रांतों में भी बिखरे हुए हैं जिसे अक्सर 'ऐतिहासिक तिब्बत' कहा जाता है। गेगु में आत्मदाह या हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन कई तिब्बतियों का कहना है कि उन्हें आर्थिक अवसरों और उम्मीदों से वंचित किया जा रहा है। गौरतलब है कि 14 अप्रैल, 2010 को आए 6.9 पैमाने के भूकंप से

गेगु बर्बाद हो गया था और इसके 80 फीसदी निवासियों को गंदे शिविरों में शरण लेना पड़ा था। हजारों लोग अब भी अपने बर्बाद मकान के सामने बने टेंट में या खुले में घोड़ों के रहने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाली जगहों पर पेयजल और बिजली के बिना जीवन गुजारने को मजबूर है। कई सरकारी इमारतों को फिर से खड़ा कर दिया गया है, लेकिन आवासीय इलाके ऐसे ही बर्बाद पड़े हुए हैं और कई लोग तो एक नहर के किनारे मलबों के बीच रहने को मजबूर हैं जिसके आसपास मानव मल और कूड़ा–करकट भी देखे जा सकते हैं। बाओबाओ चीन की जनमुक्ति सेना का जवान रह चुका है। बाओबाओ ने कहा, "मैंने देश के सचिव से कह दियाः तुम सब डकैत हो। तुम जले हुए घरों को लूट रहे हो।" बाओबाओ और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 12 अप्रैल को विनाश के करीब दो दो साल बाद सरकार ने उस चौराहे पर आठ सदस्यों के दंगा निरोधक दस्ते को तैनात कर दिया जहां प्रदर्शनकारी मौजूद हैं ताकि प्रदर्शनकारी डर से वापस चले जाएं। लेकिन प्रदर्शन अब भी निर्बाध रूप से जारी हैं। प्रशासनिक सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि उसे स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। बाओबाओ ने बताया कि वह एक मात्र ऐसा निवासी है जिसे मकान के लिए 2,20,000 युआन का मुआवजा देने का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन यह भी उसके मकान के बाजार मूल्य 8 लाख यूआन से बहुत कम है। 63 साल के एक पूर्व नोमेड जामड्रोल ने बताया कि मार्च, 2011 में करीब 4,000 तिब्बतियों ने अपने जमीन को हड़पे जाने के विरोध में प्रांत की राजधानी की ओर जाने वाली सड़क को जाम कर दिया था। इस जाम के तीसरे दिन पुलिस ने आकर जबरन जाम को हटाया और कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

हान लोगों की बाढ़

इको–टूरिज्म की योजना से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इलाके में हान चीनियों को बड़े पैमाने पर बसाया जाएगा जिनमें से कई तिब्बती जानने वाले भी होंगे। बीजिंग में रहने वाली तिब्बती लेखिका वुएजर ने बताया, "यदि बड़े पैमाने पर लोगों को बसाने की यह योजना कारगर हुई तो यह स्थानीय तिब्बतियों के परंपरागत संस्कृति पर इसका व्यापक असर होगा।" हालांकि, स्थानीय तिब्बतियों का कहना है कि उन्हें सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिली है, लेकिन ज्यादातर लोग पुनर्निर्माण की गति और नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। तिब्बतियों का कहना है कि सरकार स्थानीय लोगों को अपने मकान फिर से बनाने की इजाजत नहीं दे रही है। चीनी कंपनियों द्वारा बनाए जाने वाले ज्यादातर स्कूलों, अस्पतालों और इमारतों में चीनी मजदूरों को लगाया जाता है और ऐसे ज्यादातर मजदूर सिचुआन प्रांत से आए हैं। इस बारे में सरकारी अधिकारियों से बार–बार फोन करने के बावजूद उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। गेगू समुद्र तल से करीब 4,000 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत के ऊंचे इलाकों में से है। युशु प्रशासनिक क्षेत्र में रहने वाले करीब 3.80 लाख निवासियों में से ज्यादातर तिब्बती हैं और इनमें कई पहले नोमैड रह चुके हैं जो कि क्विंघई के सबसे गरीब समुदायों में से है। क्विंघई चीन का तीसरा सबसे गरीब प्रांत है। एक पूर्व नोमैड आमदो ने बताया कि भूकंप के बाद सरकारी अधिकारियों ने उससे कहा कि उसके पांच एकड़ घास भूमि का सरकार अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई। अधिकारियों ने इसके पहले साल 1995 में ही आमदो से वायदा किया था कि वह उसे मुफ्त में मकान और धन देंगे, इसके बदले उसने अपने पशुओं को छोड़ दिया था और पास के कस्बे में जाकर बस गया था। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भेड़ के चमड़े से बनी हुई पोशाक पहने आमदो ने कहा,"मैंने सरकार से मकान की समस्या हल करने का निवेदन किया लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है।" एक और बंजारे 56 साल के त्रिनले ने बताया कि भूकंप के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अधिकारियों ने घासभूमि पर स्थित उसके मकान को ढहा दिया।उसके परिवार को गेगू के बाहरी इलाके में बनी पुनर्वास बस्ती के एक 80 वर्ग मीटर वाले मकान में भेजा गया। सरकार ने ऐसे 70,000 मकान बनाए हैं। गेगू के कृषि एवं पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बंजारों को नई जगह बसाने से उनकी संस्कृति और धार्मिक विश्वास पर कोई भी आंच नहीं आएगी। ली सरनेम के एक अधिकारी ने फोन पर बताया,"ज्यादातर किसान और नोमैड इस पुनर्वास योजना के समर्थन में हैं।" लेकिन नीदरलैंड स्थित अंतरराष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन केंद्र में ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ एंड्रयू फिशर ने कहा कि यह नीति एक गलत कल्पना पर आधारित है। उन्होंने कहा, "नोमैड एक हद तक समृद्ध सह अस्तित्व आधारित ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। इसलिए यह मानना उनके गरिमा का अपमान ही है कि वे बाजारों में भीड़ में बैठकर अन्य स्थानीय व्यापारियों की तरह ब्रेड या कुछ और बेच सकते हैं।" कई तिब्बती लोगों का भी मानना है कि उन्हें इस योजना से कोई फायदा नहीं हुआ है। 35 साल के पूर्व नोमैड टाशी निमा को तो अब अपने परिवार का पेट पालने में मुश्किल आ रही है। एक दुकान के बाहर कुछ सामान बेच रहे टाशी ने कहा कि यदि सरकारी नीति बदलती है तो वह फिर से पशुपालन के अपने पुश्तैनी धंधे में वापस जाना चाहेगा।जामड्रोल ने बताया कि पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी के बाद अपने मकान के बाहर 20 वर्गमीटर के टेंट में बने दो कमरों में उसका जीवन कठिन साबित हो रहा है। टेंट के अंदर लकड़ी के बेंच रखे हुए हैं जिनमें कालीन की पट्टियां लगी हैं। उनकी पत्नी सेल्हा आग

आत्मदाह करने वाले बहुत से लोगों की वेदना और दुःख को सामने ला दिया है जो तिब्बती संघर्ष पर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि आत्मदाह करने वाले लोग भी हमारे, आपकी तरह मनुष्य हैं जो अपना जीवन जीना चाहते हैं।

जो इलाके हमारे दोनों पड़ोसी देशों ने हथिया रखे हैं

सेंकने के लिए लकड़ियां काट रही हैं। सरकार उनके जमीन का अधिग्रहण कर सकती है, लेकिन जामड्रोल को इससे कोई डर नहीं है। जामड्रोल ने कहा, "मैं लगातार सरकार से यह कहता रहूंगा कि यह जमीन मेरी है। वे मेरी जान भी ले लें तो भी मैं अपनी जमीन नहीं छोडूंगा।"

(बीजिंग के न्यूजरूम से अतिरिक्त रिपोर्टिंग, संपादन केन विल्स और रोन पोपेस्की द्वारा)

आत्मदाह जीवन की बर्बादी है, लेकिन तिब्बतियों का समर्थन जरूरी हैः लोबसांग सांगे

(सीएनबीसी, मनी कंट्रोल डॉट कॉम, 9 अप्रैल)

देशभक्तिपूर्ण पुनर्शिक्षा" के गहन सत्रों में शामिल किया जा रहा है और जो लोग इसमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते उन्हें मठ से हटा दिया जा रहा है।"

ऐसे समय में जब दिल्ली में चौथे ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ की यात्रा के विरोध में देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तिब्बत में स्वायत्तता के लिए 50 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 27 साल के जामफेल येशी ने आत्मदाह कर लिया। निर्वासित तिब्बती प्रशासन के प्रधानमंत्री *लोबसांग सांगे* ने *सीएनबीसी–टीवी 18* की अनुराधा सेनगुप्ता से तिब्बतियों के संघर्ष के बारे में बात की और इसके बारे में बताया कि मौजूदा पीढ़ी के लिए क्या भविष्य हो सकता है। सीएनबीसी–टीवी18 पर प्रसारित उनके इंटरव्यू के संपादित अंश यहां हम दे रहे हैं।

जामफेल येशी की मौत से तिब्बती आंदोलन को क्या हासिल हुआ?

जामफेल येशी के बलिदान ने कुछ हद तक आत्मदाह करने वाले बहुत से लोगों की वेदना और दुःख को सामने ला दिया है जो तिब्बती संघर्ष पर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मैं हमेशा यह कहता रहा हूं कि आत्मदाह करने वाले लोग भी हमारे, आपकी तरह मनुष्य हैं जो अपना जीवन जीना चाहते हैं।

लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि तिब्बती समुदाय के एक राजनीतिक नेता होने के नाते आप ऐसे चरम कार्यों को रोकने के लिए कुछ और कदम उठा सकते थे। दलाई लामा और आपने अक्सर आत्मदाह को नामंजूर किया है, लेकिन इस पर मौन स्वीकार्यता दिख रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप युवाओं को आत्मदाह के खिलाफ सलाह देने के लिए कुछ और कर सकते हैं?

कई वजहों से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमने इस तरह के बयान और निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक विरोध कानूनी, शांतिपूर्ण और गरिमा के साथ होना चाहिए। हमने कभी भी आत्मदाह को प्रोत्साहित नहीं किया है और लोगों से कहा है कि वे खास तौर से इस तरह के चरम उपायों से दूर रहें। लेकिन जब येशी जैसे व्यक्ति तिब्बत और तिब्बत के लोगों के लिए जान देते हैं तो हमें उनके साथ एकजुटता दिखानी पड़ती है और यह सुनिश्चित करना होता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए ताकि उनका जान देना व्यर्थ न हो जाए। इस तरह हमारी भूमिका जटिल है।

साल 2008 से ही आप और परमपावन दलाई लामा काफी स्पष्ट तौर पर यह कहते रहे हैं कि इन आत्मदाह की जिम्मेदारी चीन को लेनी चाहिए और इसे रोकने का उपाय भी उसे ही तलाशनी होगा। लेकिन अब भारत में विरोध प्रदर्शन के लिए आत्मदाह पर आप क्या कहेंगे, जबकि आपका कहना है कि आपने ऐसा न करने का निर्देश दिया है?

हमारे निर्देशों का कोई असर नहीं हो रहा है क्योंकि तिब्बत के भीतर होने वाला दमन काफी दर्दनाक है। गत नवंबर माह में जब 6 से 8 आत्मदाह के मामले सामने आए मैं अमेरिका गया और मैंने अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस सदस्यों से कुछ करने का आग्रह किया। हिलेरी क्लिंटन के साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किए। 3–4 नवंबर को आत्मदाह का सिर्फ एक मामला हुआ। इसके बाद मैं समूचे यूरोप के सात देशों के 11–12 दिन के दौरे पर गया और हर देश ने इस बारे में चिंता जताते हुए बयान जारी किए और मेरी इस समूची यात्रा के दौरान तिब्बत में आत्मदाह का कोई मामला सामने नहीं आया। इससे शायद ऐसा लगता है कि जब आप यह संदेश देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बतियों के लिए चिंतित है तो तिब्बती जनता को सांत्वना मिलती है।

आत्मदाह से प्रकट होता है चीन के खिलाफ तिब्बतियों का गुस्सा

उत्पीड़न ने शरणार्थियों की पहचान की भावना को प्रबल किया

(वाशिंगटन पोस्ट, 3 अप्रैल, धर्मशाला)

उसने उस ग्रामीण मठ का तीन बार परिक्रमा किया जिसमें वह बचपन में ही शामिल हुआ था, कस्बे में साइकिल से घूमा और एक दोस्त के साथ सामान्य शाकाहारी खाना खाया। इसके बाद 22 साल के लोबसांग जामयांग ने बताया कि वह टॉयलट जा रहा है। टॉयलट के अंदर उसने अपने ऊपर पेट्रोल झिड़क लिया और जब वह टॉयलट से बाहर निकला तो आग की लपटों से घिर चुका था। इसके बाद जामयांग कुछ

कदम दौड़कर पूर्वी तिब्बत के शहर नाबा के केंद्र में स्थित एक चौराहे पर पहुंच गया और विशाल मुख्य कीर्ति मठ के सामने खड़े होकर 'तिब्बत को चीन से आज़ाद करने' और निर्वासित धार्मिक नेता 'दलाई लामा को वापस लाने' का नारा लगाया। इस तनावग्रस्त और सैनिकों के भारी जमावड़े वाले शहर में पुलिस ने उसके शरीर की आग बुझाने से पहले उसे पैरों से धक्का मारा और कील लगे हुए मुदगर से पिटाई की। भारत के पहाड़ी शहर धर्मशाला स्थित शरणार्थी संगठनों द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों से हासिल खबरों से यह जानकारी मिली है। जामयांग उन 33 से ज्यादा तिब्बतियों में से एक हैं जिन्होंने चीनी शासन के खिलाफ प्रतिरोध की हाल में उठी लहर का अनुसरण करते हुए खुद को आग लगा लिया। यह आत्मदाह उस चीनी दमन की प्रतिक्रिया है जो बहुत से तिब्बतियों के अनुसार उनकी संस्कृति को नष्ट करने, उनकी आवाज़ को बंद करने और उनकी पहचान को खत्म करने का लगातार प्रयास है। साल 2008 में समूचे तिब्बती क्षेत्र में चीनी दमन में भारी बढ़त हुई है। जामयांग के एक करीबी दोस्त ने बताया कि अपनी मौत से पहले जामयांग ने अपने दोस्तों को तीन मैसेज भेजे थे। एक मैसेज यह था कि उसके गांव के तिब्बतियों को मंदारिन के हमले से अपनी भाषा को बचाने के लिए कठोर परिश्रम करना चाहिए। दूसरे मैसेज में उन्होंने हाल में तलाक लेने वाले अपने गांव के एक जोड़े से अनुरोध किया था कि वे फिर से एक साथ हो जाएं। अपनी मातृभूमि से निवार्सित होकर धर्मशाला आ चुके जामयांग के दोस्त ने बताया, "तीसरे संदेश में उन्होंने कहा था कि तिब्बतियों को चीन का सामना मजबूती से करना चाहिए, तिब्बतियों को कायर नहीं बनना चाहिए और चुप नहीं बैठना चाहिए।" जामयांग के इस दोस्त का अब भी अपने गांव के स्थानीय लोगों से अच्छा संपर्क बना हुआ है। आज धर्मशाला दलाई लामा के साथ हजारों तिब्बतियों का घर बन चुका है जो 1959 में एक जनक्रांति के विफल रहने के बाद निर्वासित होकर भारत आ गए थे। इस जनक्रांति को बुरी तरह कुचल दिया गया था। साल 2008 की वसंत में जब बीजिंग ओलंपिक करीब था, तिब्बत में एक बार विरोध प्रदर्शनों और दंगों की श्रृंखला शुरू हो गई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन विरोध प्रदर्शनों को बर्बर तरीके से कुचला गया। तिब्बती नोमैड (घुमंतु समुदायों) को अपार्टमेंट या कॉन्क्रीट के मकानों में बसाने या उनके विशाल घास मैदानों को बाड़े से घेर देने का अभियान तेज कर दिया गया है, स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में तिब्बती की जगह चीनी भाषा ज्यादा से ज्यादा लागू की जा रही है और बौद्ध मठों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण सख्त कर दिया गया है। हाल में तिब्बत से भागकर धर्मशाला आए शरणार्थियों और इस साल चीन के क्विंघई प्रांत में स्थित अपने गांव के रिश्तेदारों से मिलकर वापस लौटे शिक्षक केलसांग निमा जैसे लोगों ने बताया कि चीन सरकार के इन सख्तियों से तिब्बतियों में अपनी राष्ट्रीय पहचान की भावना और बलवती हुई है। समूचे तिब्बती पठार में फैले सभी तिब्बती लोग हफ्ते में एक दिन परंपरागत तिब्बती पहनावा पहनते हैं, केवल तिब्बती बोलते हैं और हान चीनी अधिवासियों द्वारा चलाए जा रहे दुकानों से सामान नहीं खरीदते। इस विरोध अभियान को 'सफेद बुधवार' नाम दिया गया है। फरवरी, 2009 में पूर्वी तिब्बत के सबसे प्रभावशाली मठों में से एक कीर्ति मठ के एक युवा भिक्षु तापे ने तिब्बती झंडा लहराते और हाथ में दलाई लामा की तस्वीर लिए अपने शरीर में आग लगा ली। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गोली मार दिया जिससे उनकी मौत हो गई। चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित इस मठ को साल 1997 से ही लगातार बढ़ते सुरक्षा घेरे का सामना करना पड़ रहा है। तबसे भागकर भारत आए और यहां रह रहे एक भिक्षु लोबसांग येशी ने बताया, "मठ के भिक्षुओं को "देशभक्तिपूर्ण पुनर्शिक्षा" के गहन सत्रों में शामिल किया जा रहा है और जो लोग इसमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखाते उन्हें मठ से हटा दिया जा रहा है।" येशी के अब भी मठ के अपने पुराने साथियों से संपर्क बने हुए हैं। मठ के भिक्षुओं में इस बात को लेकर थोड़े मदभेद हैं कि इस सख्ती पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। येशी ने बताया, "पुरानी पीढ़ी के लोग जिन्होंने सांस्कृतिक क्रांति देखी है, जब तिब्बत के मठों को काफी हद तक नष्ट और खाली कर दिया गया था, जो यह जानते हैं कि चीन कुछ भी कर सकता है, वे सरकार से सहयोग करने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी के लोग इसका प्रतिरोध करना चाहते हैं। दलाई लामा का कहना है कि वह आत्मदाह की अनदेखी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने काफी हद तक इन विवादों से अपने को दूर रखा है क्योंकि वे पिछले साल राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित निर्वासित सरकार को अपनी राजनीतिक सत्ता सौंप दी है जिसके मुखिया हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर लोबसांग सांगे हैं।

कुल 22 पेज के इस प्रजेंटेशन में चीन की राजनीति-सैन्य आक्रामकता और पाकिस्तान को मिल रहा उसका समर्थन खासकर उत्तरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास का भी उल्लेख किया गया है।

परमाणु पनडुब्बी ने भारत को बड़े लीग में रखा तो अग्नि–5 ने और आगे पहुंचाया

(एचटी, 5 अप्रैल, नई दिल्ली–विशाखापत्तनम)

रूस से परमाणु ताकत वाली पनडुब्बी आईएनएस चक्र हासिल करने और इसे बुधवार को नौ सेना में शामिल करने के बाद भारत अब 15 अप्रैल को 5,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाले अग्नि–5 मिसाइल का परीक्षण कर अपनी सामरिक सुरक्षा को और मजबूत करने जा रहा

वह तिब्बत आंदोलन के प्रबल समर्थक थे।

(1)

(2)

(10)

कैमरे की आंख

1. शिकागो में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के 12वें विश्व सम्मेलन के दौरान नोबेल शांति पुर
लामा और कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सांगे।
2. पूर्वी तिब्बत के जोगछेन, देगे में चीन सरकार के कार्यालय के बाहर 25 अप्रैल, 2012 क
3. वीडियो क्लिप से ली गई इस तस्वीर में 14 जनवरी, 2012 को नाबा में आग की लपटो
4. धर्मशाला में 16 अप्रैल को तिब्बती शहीदों के सम्मान में तिब्बती ट्रांजिस्ट स्कूल के विद्या
5. प्रख्यात समाजवादी नेता, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और राज्य सभा सदस्य 72 साल के श्री बृज
6. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.वी. सदानंदा गौड़ा के साथ कालोन ग्यारी डोलमा और श्री टाश
7. उत्तर भारत के शहर धर्मशाला में 22 अप्रैल, 2012 को विश्व पृथ्वी दिवस पर आयोजित
8. कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी धोनडुप फुंसोक ने तिब्बत पर जारी चीनी
9. सीनेटर डियाने फीनस्टीन (बाएं) और सीनेटर जोसेफ लिबरमैन (दाएं)।
10. चीन के अंधे अधिकारी छेन गुआंगछेंग।

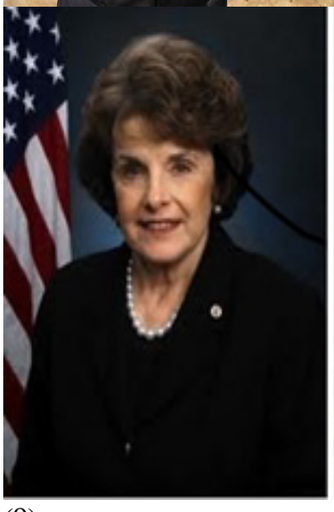

(9)

(8)

आंखों देखी

(3)

(4)

(5)

मरे की आंख से

रान नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति लेक वालसा के साथ परमपावन दलाई

र 25 अप्रैल, 2012 को हो रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हजारों तिब्बतियों ने हिस्सा लिया।

बा में आग की लपटों में घिरा लोसांग जामयांग का शरीर दिख रहा है। (आईसीटी)

जिस्ट स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा बनाए विशाल प्रार्थना चक्र को घुमाते 17वें ग्यालवांग करमापा।

72 साल के श्री बृजभूषण तिवारी जिनका हाल में निधन हो गया।

डोलमा और श्री टाशी फुंस्तोक।

दिवस पर आयोजित पर्यावरण रैली का नेतृत्व करते स्कूली छात्र।

तिब्बत पर जारी चीनी कब्जे के विरोध में गत 2 अप्रैल को हावड़ा पुल से नीचे छलांग लगा ली।

ं)।

(फोटो परिचय : ऊपर बाएं से घड़ी की दिशा में)

(7)

(6)

पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी रक्षा तैयारियों के लिए हर साल 180 अरब डॉलर खर्च कर रहा है।

है। परमाणु क्षमता वाली इस मिसाइल की पहुंच के दायरे में बीजिंग भी होगा और यह चीन को एक मजबूत प्रतिरोधी संकेत देने के लिए तैयार किया गया है जोकि तिब्बत और सीक्यांग इलाकों में भारत केंद्रित मिसाइलों और सैन्य बलों की अन्य क्षमताओं में विस्तार कर रहा है। 50 टन और 17.5 मीटर लंबी और दो मीटर व्यास वाली तीन चरणों वाली यह ठोस मिसाइल मल्टिपल इंडीपेन्डेंट टारगेटेबल री इंट्री व्हीकल (एमआईआरवी) से लैस है। इसका मतलब यह है कि यह एक मिसाइल एक साथ कई इलाकों में एक टन के परमाणु हथियार के साथ हमला कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीओ) की पहले योजना यह थी कि आईएनएस चक्र को हासिल करने के साथ ही अग्नि–5 का परीक्षण किया जाए, लेकिन बाद में यह परीक्षण टाल दिया गया। आईएनएस चक्र को बुधवार को नौसेना में शामिल किया गया। इसे 1 अरब डॉलर (5,000 करोड़ रुपए) में 10 साल के लिए लीज पर हासिल किया गया है। हालांकि, अपने मौजूदा स्वरूप में चक्र परमाणु हथियार नहीं ले जा सकता। यह टॉरपीडो, जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल ढो सकता है। भारत का नाभिकीय त्रिकोण (जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियार छोड़ने की क्षमता) तब ही पूरा होगा जब वह अपनी सेना में स्वदेशी नाभिकीय क्षमता वाली पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत को शामिल करेगा। इसे इस साल परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा जाएगा। अरिहंत समुद्र के भीतर से छोड़े जा सकने वाले के–15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगा और यह 700 किलोमीटर की दूरी तक परमाुण हथियार का हमला कर सकेगा।

चीन द्वारा पाकिस्तान में हो रहा सैन्य निर्माण और उसको सहयोग भारत के लिए मुख्य खतरा

भारत का प्रतिरक्षा बजट बढ़ाकर चीन के अनुरूप किया जाना चाहिए।

(डीएनए, 5 अप्रैल, नई दिल्ली)

चीन द्वारा सेना का आधुनिकीकरण और पाकिस्तान को उसके लगातार समर्थन जैसे उत्तरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास आदि को थल सेना ने भारत के लिए बड़े खतरों की सूची में रखा है। पीटीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रतिरक्षा पर संसद की स्थायी समिति के सामने अनुदान मांगों को लेकर पेश विस्तृत प्रस्ताव में सेना के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस. के.सिंह ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि पाकिस्तान में लगातार जारी अस्थिरता और वहां का आतंकवादी ढांचा भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। चीन को देश के लिए बड़े खतरों में से एक बताते हुए सेना ने अपने प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख किया है कि उसके साथ भारत के सीमा संबंधी कई अनसुलझे मसले हैं और चीन को खतरा मानने का आधार उसके द्वारा तिब्बत में किया जा रहा बुनियादी ढांचा विकास और ऐसी आंतरिक सड़कों का निर्माण है जिसके द्वारा वह पड़ोसी देशों तक तत्काल पहुंच सकता है।

कुल 22 पेज के इस प्रजेंटेशन में चीन की राजनीति–सैन्य आक्रामकता और पाकिस्तान को मिल रहा उसका समर्थन खासकर उत्तरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास का भी उल्लेख किया गया है। पाकिस्तान को 'आतंकवाद का केंद्र' बताते हुए इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पाक लगातार भारत के खिलाफ छद्म युद्ध को सहयोग दे रहा है और उसकी जमीन पर आतंकवादी ढांचा अब भी बरकरार है। सेना ने सांसदों को बताया है कि वह भय के द्वारा ही युद्ध को रोकने की इच्छा रखती है और किसी युद्ध की दशा में एक सक्रिय जवाब देने के लिए उसके पास क्षमता होनी चाहिए। सेना ने अगले वित्त वर्ष के लिए एक अनुमानित आधुनिकीकरण योजना भी तैयार की है जिसमें इसकी विभिन्न शाखाओं को आवंटन की रूपरेखा पेश की गई है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री एंटोनी से सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना को मजबूत बनाने का अनुरोध किया

(बिजनेस स्टैंडर्ड, 7 अप्रैल, देहरादून)

केंद्रीय रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी प्रतिरक्षा ढांचा मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नई दिल्ली में गुरुवार को देर रात हुई एक बैठक में एंटोनी ने राज्य के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को इस बात का भरोसा दिया है। बहुगुणा ने रक्षा मंत्री से सीमावर्ती क्षेत्रों में हवाई अड्डे एवं हेलीपैड के निर्माण का भी अनुरोध किया है। गौरतलब है कि तिब्बत में चीन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है जिसकी वजह से भारतीय सेना ने भी उत्तराखंड में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की है और 13 नए हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। इस उद्देश्य से सेना ने राज्य सरकार से मांग की है कि वह सामरिक महत्व को देखते हुए विभिन्न प्रतिरक्षा परियोजनाओं के लिए पहाड़ी राज्य में 23,216 एकड़ जमीन उपलब्ध करे। राज्य के मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने इस संबंध में फरवरी में यहां सचिवालय में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। सेना राज्य में 13 नए हेलीपैड का निर्माण करेगी। इसके अलावा सेना अल्मोड़ा, बनबासा, धारचुला, देहरादून, धरासू, चरमागॉर्ड, छियालेख, गुंजी, घतौली, घंसाली, औली, हलद्वानी, पंतनगर और पिथौरागढ़ क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू करेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना उत्तराखंड में अपने को ऐसे समय में मजबूत

करना चाहती है जब चीन दलाई लामा के समर्थकों के बवाल के डर से तिब्बत में अपनी सेना की संख्या को पहले ही बढ़ा चुका है।

चीन के कृत्य उत्तर–पूर्व के लिए विनाशक हो सकते हैं

(आर. दत्ता चौधुरी, असम ट्रिब्यून डॉट कॉम, गुवाहाटी, 8 अप्रैल)

प्रख्यात सुरक्षा विश्लेषक मेजर जनरल (रिटायर्ड) जी. डी. बख्शी का मानना है कि पानी के लिए होने वाला युद्ध उत्तर–पूर्व इलाके के लिए सबसे बड़े संकट में से एक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का प्रतिरक्षा बजट बढ़ाकर चीन के अनुरूप किया जाना चाहिए। दि असम ट्रिब्यून से बात करते हुए मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि यदि चीन ब्रह्मपुत्र के जल धारा की दिशा मोड़ने का निर्णय लेता है तो इसका भारत के उत्तर–पूर्वी इलाके पर काफी विनाशक असर होगा। खबरों के अनुसार चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर 28 बांध परियोजनाएं बना रहा है और वैसे तो चीन का दावा है कि इन परियोजनाओं से नदी के प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गर्मियों के मौसम में निश्चित रूप से इसकी जलधारा सूख जाएगी और बरसात के मौसम में यह काफी विनाशक रूप ले लेगी।

मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि चीन जल की भारी कमी का सामना कर रहा है, खासकर देश के उत्तरी इलाके में और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि पड़ोसी देश अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्मपुत्र की धाराओं की दिशा को ही मोड़ दे। प्रतिरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि ऐसी परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि चीन अब म्यांमार के कछिन इलाके में एके सिरीज की राइफलें तैयार करने का कारखाना लगा रहा है। यदि यह खबरें सच साबित हुईं तो निश्चित रूप से उत्तर–पूर्व के आतंकवादी गुटों और माओवादियों को इस कारखाने से हथियार मिल सकेगा और वे अपने को मजबूत बना सकेंगे। मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि चीन लगातार हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश दौरे का विरोध करता रहा है, जिससे साबित होता है कि इस पड़ोसी देश के इरादे क्या हैं। दूसरी तरफ, चीनी नेता लगातार पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा करते रहे हैं जो कि विवादित इलाका है। प्रतिरक्षा बजट के मसले पर मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि भारत का प्रतिरक्षा बजट चीन की तुलना में काफी कम है। उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिरक्षा बजट करीब 38 अरब डॉलर का है, जबकि चीन का प्रतिरक्षा बजट 106 अरब डॉलर का है। पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार चीन अपनी रक्षा तैयारियों के लिए हर साल 180 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा, "मैं यह नहीं कह रहा कि चीन जितने डॉलर खर्च करे उतना ही डॉलर हम भी खर्च करे या वह जितना टैंक रखे, हम भी रखें, लेकिन कुछ तो समानता होनी चाहिए।" बुनियादी ढांचे के बारे में मेजर जनरल बख्शी ने कहा कि भारत के मुकाबले चीन का बुनियादी ढांचा विकास काफी बेहतर है, तिब्बत में रेल निर्माण के बाद अब चीन इस इलाके में एक सीजन में ही सेना के 34 डिवीजन को भेज सकता है, जबकि भारत इस मामले में काफी पीछे है।

चीन ने भारत के मुकाबले अपनी सैन्य क्षमता को और बढ़ाया

(हिंदुस्तान टाइम्स, 9 अप्रैल, नई दिल्ली)

रक्षा मंत्रालय की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि चीन ने भारत के मुकाबले अपने सैन्य बल तैनाती क्षमता को काफी बढ़ा लिया है। साल 2011–12 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि हमारे सटे हुए और विस्तारित पड़ोस में स्थित चीन के रूपरेखा में बदलाव के निहितार्थ पर भारत 'सचेत है और निगरानी बनाए हुए है।' मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है,"तिब्बत और सीक्यांग में तीव्र बुनियादी ढांचा विकास से चीन की सैन्य बल तैनाती क्षमता भारत के मुकाबले काफी बढ़ गई है और इससे चीन के समग्र सामरिक और कामकाजी लचीलेपन में सुधार हुआ है।" रिपोर्ट में चीन द्वारा राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहयोग के 'सक्रिय राजनय' के द्वारा भारत के पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते दखल पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अपनी पिछली रिपोर्ट में मंत्रालय ने इस बात की चेतावनी दी थी कि भारत के सुदूर सीमावर्ती इलाके (जो इलाके हमारे दोनों पड़ोसी देशों ने हथिया रखे हैं) में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एकजुट होकर काम कर रही है और इसका भारत पर सीधा सैन्य असर होगा। मंत्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है, "एक उभरती अर्थव्यवस्था के समर्थन के साथ ही चीन की बढ़ती ताकत उसके बढ़े हुए आत्मविश्वास से प्रदर्शित होती है जिसका क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की रूपरेखा एवं ताकत के संतुलन पर असर होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि समृद्ध पाकिस्तान वैसे तो भारत के ही हित में है लेकिन 'भारत–पाक सीमा पार आतंकवादी शिविरों की मौजूदगी और नियंत्रण रेखा पर लगातार घुसपैठ के प्रयास भारत के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं।"

जापान में प्रस्ताव पारित कर चीन से तिब्बत में दमन खत्म करने को कहा गया

(तिब्बत डॉट नेट, 5 अप्रैल, टोक्यो)

"हम चीन सरकार से यह आग्रह करते हैं कि वह धर्म या विश्वास की आज़ादी के लिए गठित विशेष रैपोर्टियर (प्रतिवेदक) के दौरे के अनुरोध पर सकारात्मक तरीके से विचार करे और तत्काल मानवाधिकारों का दमन रोके।

चीन से बढ़ती करीबी का साफ संकेत देखते हुए प्रतिबंधित यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के परेश बरुआ गुट ने असम में तिब्बती आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों द्वारा हाल में किए गए चीन विरोधी प्रदर्शनों की पहली बार कड़ी आलोचना की है।

कालोन ट्रिपा के जापान दौरे के अंतिम दिन बुधवार को जापान के पांच राजनीतिक दलों से जुड़े 60 सांसदों ने एक प्रस्ताव पारित कर तिब्बत में तिब्बतियों के दुःखद आत्मदाह की घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और चीन सरकार से आग्रह किया कि वह तिब्बतियों की शिकायतों को दूर कर वहां अपनी दशकों से जारी दमनकारी नीतियों को खत्म करे। प्रस्ताव में कहा गया है, "हम चीन सरकार से यह आग्रह करते हैं कि वह धर्म या विश्वास की आज़ादी के लिए गठित विशेष रैपोर्टियर (प्रतिवेदक) के दौरे के अनुरोध पर सकारात्मक तरीके से विचार करे और तत्काल मानवाधिकारों का दमन रोके। तिब्बतियों के अधिकारों पर वर्षों से जारी प्रतिबंध ा ही आत्मदाह के द्वारा विरोध प्रदर्शन की वजह हैं। साफतौर पर चीन सरकार के लिए ऐसा समय आ गया है कि वे बुनियादी तौर पर अपने रवैए पर पुनर्विचार करें और तिब्बतियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करें।" प्रस्ताव में कहा गया है, "हमारा मानना है कि यदि चीन तिब्बतियों के अधिकारों का सम्मान कर एक वास्तव में 'समरस समाज' को साकार करता है तो जापान एवं चीन एक वास्तविक सार्थक सामरिक लाभ हासिल कर सकेंगे।" प्रस्ताव में जापानी सांसदों ने मार्च 2012 से ही तिब्बत में जारी आत्मदाह के अनवरत सिलसिले पर गहरी चिंता जताई है। प्रस्ताव में चीन सरकार से आग्रह किया गया है कि वह मठों पर लगे प्रतिबंधों और देशभक्ति पुनर्शिक्षा युक्ति को खत्म कर तिब्बत में बुनियादी मानवाधिकारों का दमन रोके। इसमें चीन सरकार से यह भी आग्रह किया गया है कि वह इस बात की साफ तौर पर जानकारी दे कि आत्मदाह की घटनाओं के सिलसिले में गिरफ्तार तिब्बती भिक्षुओं एवं आम व्यक्तियों को कहां रखा गया है और उनकी मौजूदा हालत कैसी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मीडिया एवं विदेशी पर्यटकों को तिब्बती इलाकों में घूमने–फिरने की आज़ादी दी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया है कि चीन सरकार और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के बीच प्रत्यक्ष और परिणाम उन्मुख संवाद होना चाहिए।

कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सांगे ने सांसदों को तिब्बत के हालात के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने उनके सवालों के जवाब भी दिए। सांसदों के साथ बैठक में उपस्थित जापान में परमपावन दलाई लामा के प्रतिनिधि श्री ल्हाकपा शोको ने कहा, "जापान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ उसके सांसदों ने मिलकर तिब्बत में तात्कालिक हालात पर चर्चा की हो और उस पर गहरी चिंता जताते हुए उसके बारे में एक प्रस्ताव पारित किया हो। उन्होंने तिब्बत मसले के अच्छे भविष्य के बीज बो दिए हैं।" इसके बाद शाम को कालोन ट्रिपा ने "ग्लोबल वार्मिंगः तिब्बत के नाजुक पर्यावरण पर विशेष जोर के साथ" विषय पर एक व्याख्यान दिया। जापान के अपने पहले पांच दिवसीय दौरे पर गए कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सांगे जापान के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों, टोक्यो के गवर्नर, सांसदों, पत्रकारों और आम जनता से मिले और उन्हें तिब्बत के गंभीर हालात की जानकारी दी तथा जापानी जनता से यह निवदेन किया कि वे तिब्बत को अपना समर्थन जारी रखें। कालोन ट्रिपा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के निमंत्रण पर जापान की यात्रा पर गए थे। पिछले साल भारत दौरे पर अपने व्यस्त कार्यक्रम के दौरान श्री एबे ने अपने प्रतिनिधि को धर्मशाला भेजकर कालोन ट्रिपा को अपनी शुभकामनाएं दी थीं और उन्हें जापान आने के लिए आमंत्रित किया था।

नोबेल सम्मानित हस्तियों ने चीनी राष्ट्रपति से तिब्बत मसले पर वार्ता करने का आग्रह किया

(पंजाब न्यूजलाइन, 4 अप्रैल, शिमला)

दुनिया के विभिन्न हिस्सों के 12 नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं ने चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ को खुला पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि वे दलाई लामा के साथ सार्थक संवाद करें। निर्वासित तिब्बती सरकार ने बताया कि हाल में तिब्बत में तिब्बती लोगों के दमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तरीके के तहत शुरू आत्मदाह के लहर को देखते हुए यह पत्र लिखा गया है। तिब्बती आत्मदाह पर गहरी चिंता जताते हुए नोबेल विजेताओं ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तिब्बत के लोगों द्वारा आत्मदाह के द्वारा असंतोष के प्रबल अभिव्यक्ति को लेकर चिंतित है और चीन सरकार को तिब्बतियों की आवाज़ को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना चाहिए और एक अहिंसक समाधान तलाशना चाहिए। इन नोबेल विजेताओं में डेसमंड टुटु, जोडी विलियम्स और लेक वालेसा जैसी हस्तियां शामिल हैं। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ से मांग की है कि वे तिब्बत को पत्रकारों और राजनयिकों के लिए खोलें, तिब्बतियों के मनमाने कैद पर रोक लगाएं और उनकी धार्मिक आज़ादी का सम्मान करें।

चीन के सख्त शासन के विरोध में मार्च, 2011 के बाद तिब्बत में 30 से ज्यादा लोगों ने आत्मदाह कर लिया है। तिब्बतियों का कहना है कि चीन की कार्रवाई इतनी ज्यादा दमनात्मक होती है कि तिब्बतियों के पास अपना विरोध जताने के लिए और कोई रास्ता नहीं बच रहा है। चीन सरकार कई दशकों से भारत में रह रहे निर्वासित तिब्बती नेता दलाई लामा पर यह आरोप लगाती रही है कि वे आत्मदाह को बढ़ावा दे रहे हैं और उसने इस तरह से विरोध प्रदर्शन की कार्रवाई को आतंकवाद बताया है। निर्वासित तिब्बती सरकार ने चीन सरकार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

अमेरिका ने नेपाल से तिब्बती शरणार्थियों को पंजीकृत करने को कहा

अमेरिका ने नेपाल से कहा है कि वह तिब्बती शरणार्थियों का नए सिरे से पंजीकरण चालू करे

(डीपीए)

नेपाल में 1990 की पिछली जनगणना के बाद बहुत से और तिब्बती आ चुके हैं और बहुत से तिब्बती बच्चों का जन्म हुआ है। इससे वहां उनकी संख्या 20,000 के आसपास पहुंच गई है। इनमें से सैकड़ों लोगों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। काठमांडू पोस्ट में छपी खबर के अनुसार अमेरिकी विदेश विभाग में राजनीतिक मामलों के अवर सचिव वेंडी आर. शर्मन प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई से मिले और उनसे यह मांग की कि निर्वासित तिब्बती बच्चों को रोजगार एवं शिक्षा हासिल करने के रास्ते में आने में बाधाओं को दूर किया जाए। शर्मन ने कहा, "हमने प्रधानमंत्री से तिब्बतियों के पहचान पत्र और उनके पंजीकरण के बारे में लगातार बात किया है। इस बात को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होनी चाहिए कि यहां की सरकार शरणार्थियों के अंतरराष्ट्रीय अधिकारों का समर्थन करती है और मैं जानता हूं कि यह तिब्बती शरणार्थियों के अन्य बचे हुए मसलों का भी समाधान करेगी।" तिब्बती शरणार्थियों को लेकर नेपाल को परस्पर विरोधी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी देश यह चाहते हैं कि शरणार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार हो और नेपाल ने इन शरणार्थियों को सुरक्षित भारत तक रास्ता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र से अनौपचारिक समझौता भी किया है। लेकिन नेपाल सरकार पर चीन की तरफ से इस बात के लिए लगातार दबाव आ रहा है कि वह अपनी जमीन पर शरणार्थियों को नियंत्रित करे और उन्हें तिब्बत पर चीनी कब्जे के खिलाफ किसी तरह के प्रदर्शन से रोके।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने बृजभूषण तिवारी के निधन पर शोक जताया

(तिब्बत डॉट नेट, 25 अप्रैल, नई दिल्ली)

प्रख्यात समाजवादी नेता और राज्य सभा सदस्य 72 वर्षीय बृजभूषण तिवारी का हृदय गति रुक जाने से बुधवार सुबह दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में निधन हो गया। बृजभूषण ने मंगलवार को ही सांसद के रूप में शपथ लिया था। वह तिब्बत आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। बृजभूषण तिवारी पांचवीं बार समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए थे। सबसे पहले वह 1977 में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और साल 2006 से ही दो बार राज्य सभा सांसद चुने गए। वह तिब्बत पर *अखिल भारतीय संसदीय मंच* और *तिब्बत पर सांसदों के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क* (आईएनपीएटी) के सदस्य थे। वह वाशिंगटन एवं रोम में आयोजित तीसरे एवं चौथे *तिब्बत पर विश्व सांसद सम्मेलन* (डब्ल्यूपीसीटी) में भी शामिल हुए थे और उन्हें इस साल कनाडा के ओटावा में आयोजित होने वाली डब्ल्यूपीसीटी में भी हिस्सा लेना था। वह मौजूदा कालोन ट्रिपा डॉ. लोबसांग सांगे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और उन्होंने तिब्बत एवं तिब्बती आंदोलन के बारे में आयोजित कई सम्मेलनों में हिस्सा लिया था। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को श्री बृजभूषण तिवारी के अचानक निधन पर गहरा दुःख हुआ है जो लंबे समय से तिब्बती जनता और तिब्बत आंदोलन के मित्र रहे हैं। बृजभूषण तिवारी अपने पीछे पत्नी, दो बेटों और दो बेटियों को छोड़ गए हैं। निर्वासित तिब्बत संसद के सदस्य आचार्य येशी फुंसोक, भारत–तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री तेनजिन नोर्बू और मजनू का टीला स्थित तिब्बती बस्ती के कई प्रतिनिधि श्री तिवारी को श्रद्धांजलि देने और तिब्बत आंदोलन को उनके अटल समर्थन की याद में तिब्बती जनता की तरफ से शोक संवेदना जताने के लिए बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल और 24 कॉपरनिकस मार्ग स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में पहुंचे थे।

सुरक्षा घेरे ने इस इलाके से पत्रकारों को बाहर ही रखा है।

ग्यालवा करमापा रिनपोछे के खिलाफ केस वापस लेने के लिए कशाग ने हिमाचल सरकार का आभार जताया

(तिब्बत डॉट नेट, धर्मशाला, 26 अप्रैल)

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कशाग ने 17वें ग्यालवा करमापा उग्येन त्रिनले दोरजी के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार जताया है। कशाग ने अपने बयान मे कहा है, "इस उचित निर्णय के लिए कशाग सभी संबंधित अधिकारियों को धन्यवाद देता है। निर्वासित तिब्बती समुदाय कानून का पालन करने वाला समुदाय है और यह जिस देश में भी रहता है उसके कानून का सम्मान करता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन फिर से तिब्बती जनता से यह निवेदन करना चाहता है कि वे भारतीय कानून एवं नियमों का पालन करें।"

उल्फा की चीन से बढ़ती करीबीः बरुआ गुट ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों की आलोचना की

(हिंदुस्तान टाइम्स, 1 अप्रैल, नई दिल्ली)

चीन से बढ़ती करीबी का साफ संकेत देखते हुए प्रतिबंधित यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के परेश बरुआ गुट ने असम में तिब्बती आंदोलनकारियों और उनके समर्थकों द्वारा हाल में किए गए चीन विरोधी प्रदर्शनों की पहली बार कड़ी आलोचना की है। मीडिया को भेजे गए बयान में संगठन ने कहा है, "असम में तिब्बत आंदोलन को बढ़ता समर्थन किसी सुनियोजित योजना का हिस्सा है। यह चीन के आंतरिक

इससे चीनी नेतृत्व का भी मजाक बनता है जब वे हताशा में दलाई लामा को हिटलर या अमेरिका के नाज़ी सहयोगी के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं।

कई बार वे अपने शरीर को तेज लपटों में जलाने के लिए केरोसीन पी जाते हैं।

मामलों में पूरी तरह से दखल है।" संगठन ने स्थानीय जनता से कहा है कि वह किसी बहकावे में न आते हुए चीन विरोधी भावनाओं का समर्थन न करें। यह कहते हुए कि दलाई लामा या निर्वासित तिब्बती प्रशासन ने पिछले तीन दशकों में असम में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर कभी भी कोई चिंता जाहिर नहीं की है, संगठन ने सवाल उठाया है, "क्या हम पर तिब्बत का कोई एहसान है जिसके एवज में हम अपनी जमीन पर चीनी झंडा जलाएं?" इसके कुछ दिनों पहले ही प्रतिबंधित संगठन ने एक ई–मेल भेज कर चीनी उदाहरण को रेखांकित करते हुए एक सींग वाले गैंडे और जंगली हाथी के संरक्षण पर जोर दिया था। इस पत्र में कहा गया है, "हाथियों के संदर्भ में यह चाहिए कि असम का वन विभाग जनता और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इनके चारे के व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से तेजी से बढ़ने वाले घास, बांस, जंगली ताड़ आदि उगाए जैसा कि चीन के सिचुआन प्रांत में किया गया है।"

तिब्बतियों का आत्मदाहः दुनिया क्यों नहीं सुन रही चीख?

यह हाल के इतिहास में राजनीतिक आत्मदाह की सबसे बड़ी लहर है। लेकिन बाहरी दुनिया में इन चरम विरोध प्रदर्शनों पर बहुत गौर नहीं किया जा रहा।

विजय क्रांति

(एसएमई टाइम्स, 3 अप्रैल)

अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ज्वलंत सनसनी बनने से पहले 27 साल के जामफेल येशी की कहानी उन लाखों तिब्बतियों की कहानी से अलग नहीं थी जो आज चीनी नेताओं के तथाकथित 'समाजवादी स्वर्ग' या चीनी तिब्बत में रहते हैं। वह उन 10,000 युवा तिब्बतियों में से एक था जो हाल के वर्षों में बेहतर शिक्षा या अपनी घुटती आत्मा को सांस लेने लायक जगह देने के लिए तिब्बत से भागकर बाहर आ गए हैं। अधिकृत तिब्बत के अपने अन्य युवा देशवासियों की तरह ही जामफेल ने न तो कभी दलाई लामा को देखा था और न ही वह कभी चीन द्वारा प्रचारित उस 'दलाई गुट' के 'सामंती' शासन के तहत रहा है जिसे माओ की सेना ने जामफेल के जन्म के 36 साल पहले ही अपदस्थ कर दिया था। अपने पिता की तरह वह भी नियमित रूप से हर दिन कम्युनिस्ट ब्रेनवाश और शिक्षा के ओवरडोज के साथ बड़ा हुआ है जिसके द्वारा चीन सरकार यह उम्मीद करती है कि वह चीन में तिब्बतियों और 55 अन्य 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों' के बच्चों को 'महान मातृभूमि' के 'देशभक्त' नागरिक में बदल देगी। जामफेल को भी उसके स्कूल क क्लास टीचर ने बताया था कि दलाई लामा 'भिक्षु के रूप में एक भेड़िया' हैं और इसलिए 'अलगवादी' होने और उनके चीनी मातृभूमि के 'सबसे बड़े दुश्मन' होने के नाते उनसे घृणा करना चाहिए। हालांकि, जब जामफेल किशोरावस्था में पहुंचा और वह अपने नस्लीय इतिहास से परिचित होना शुरू हुआ तो वह भी ताउ के अपने परपंरागत खम्पा तिब्बती कस्बे में हान लोगों (चीन का बहुसंख्यक समुदाय) की बढ़ती संख्या के बीच घुटन महसूस करने लगा। तिब्बत की आज़ादी छिन जाने के बाद खम्पा कस्बे को पड़ोसी सिचुआन प्रांत में मिला दिया गया। साल 2007 में जामफेल चुपके से भारत आ गया और वह दिल्ली में एक कंप्यूटर कोर्स कर रह था कि एक दिन उसने संसद के नजदीक चीन विरोधी और हू जिनताओ के विरोध वाली तिब्बती रैली में शामिल होने के समय ही आत्मदाह करने जैसा चरम कदम उठा लिया। विशेषकर हू को तिब्बती जनता 'ल्हासा के कसाई' के रूप में जानती है। तिब्बत के गवर्नर रहने के दौरान हू ने साल 1989 में हुई तिब्बती जनक्रांति को प्रभावी तौर से कुचलने के लिए सेना के टैंकों और सशस्त्र वाहनों का इस्तेमाल किया था। इसके तीन महीने के बाद इसी 'ल्हासा मॉडल' का इस्तेमाल उनके वरिष्ठों ने टिनामेन चौक पर कम्युनिस्ट व्यवस्था के खिलाफ चीनी युवाओं की क्रांति को कुचलने के लिए किया था। पिछले एक साल में तिब्बत के भीतर और बाहर आत्मदाह कर लेने वाले जामफेल 32वें तिब्बती हैं। बुधवार को हुई उनकी मौत तिब्बतियों की इस तरह से पुष्ट तौर पर हुई 18वीं मौत है। आत्मदाह करने वाले अन्य 13 तिब्बतियों की क्या हालत है, इसके बारे में सिर्फ चीनी अधिकारी ही बता सकते हैं। जामफेल की मौत के बाद भारत सरकार ने साफ वजहों से सुरक्षा उपाय और सख्त करने का निर्णय लिया ताकि हू जिनताओ को यहां रहने के दौरान किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हू जल्दी ही चीन लौट जाएंगे और इस आत्मदाह से बना असहज वातावरण अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बाढ़ में दब कर रह जाएगा। लेकिन जामफेल की आग ने ऐसे कुछ मसले छोड़े हैं जो लोकतंत्र और सभ्य आचरण में भरोसा रखने वाले विश्व समुदाय को परेशान करते रहेंगे।

कुछ मसलों पर करना होगा विचार

तिब्बती युवाओं (जिसमें ज्यादातर भिक्षु एवं भिक्षुणी हैं) के आत्मदाह की लंबी श्रृंखला चीन द्वारा अक्सर दोहराए जाने वाले इस दावे को खारिज करती है कि तिब्बत के भीतर सब कुछ सही है या यह कि तिब्बती लोग चीनी शासन को पसंद करते हैं और 'सामंती' दलाई लामा से घृणा करते हैं। एक के बाद एक जलते एवं मरते, आत्मदाह करने वाले लोगों के 'रंगजेन' (तिब्बत की आज़ादी) और परमपावन के तिब्बत वापस लाने के नारे लगाने से दुनिया भर में हजारों यूट्यूब दर्शकों के सामने तिब्बत का वास्तविक चेहरा सामने आ गया है जो कि चीन सरकार के दावों के विपरीत है। तिब्बती युवाओं द्वारा आत्मदाह के कम से कम 32 मामले और अपने साम्राज्यवादी आकाओं के खिलाफ चाकू घोपने, गोली चलाने, बम विस्फोट या अपहरण के

एक भी मामले न होना इस बात को रेखांकित करता है कि तिब्बती लोग अपने गुरू दलाई लामा और उनके अहिंसा या गांधी के अहिंसा में गहरा विश्वास करते हैं। इससे चीनी नेतृत्व का भी मजाक बनता है जब वे हताशा में दलाई लामा को हिटलर या अमेरिका के नाज़ी सहयोगी के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। यह बात संदेह से परे है कि तिब्बत के भीतर प्रतिरोध जिंदा है और चीन के 61 साल से ज्यादा समय से कब्जे के बाद भी व्यापक रूप से फैला हुआ है, साथ ही संभवतः साल 1959 में निर्वासन के दिन के बाद से अब तक दलाई लामा और ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। यह भी सिद्ध हो गया है कि छह दशकों का कम्युनिस्ट ब्रेनवाश भी तिब्बती जनता की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को शांत करने में विफल रहा है और आज तिब्बती जनता निराशा के गर्त में धकेले जाने का अनुभव कर रही है। सभी 32 आत्मदाह की घटनाएं खम और आमदो के पूर्व तिब्बती प्रांतों में हुई हैं जो अब सिचुआन, यून्नान, क्विंघई और गांजू का हिस्सा हैं–इससे चीन के इस दावे को चुनौती मिलती है कि ये इलाके तिब्बत का हिस्सा नहीं हैं और केवल तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र ही 'असल तिब्बत' है। इन आत्मदाह की ज्यादातर घटनाओं में चीनी जन सुरक्षा बल पुलिस के जवान और एजेंटों ने जिस तरह से लपटों में घिरे व्यक्ति को पैरों से धक्का मारा है या आसपास से गुजरने वाले स्थानीय हान प्रत्यक्षदर्शियों ने मरते हुए इन युवा तिब्बतियों पर जिस तरह से पत्थरों की बरसात की है उससे पता चलता है कि तिब्बती इलाकों में स्थानीय तिब्बतियों और चीनी निवासियों के बीच गहरे मतभेद हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां ट्यूनिशिया के सिर्फ एक सब्जी विक्रेता के आत्मदाह के बाद आंदोलन को दुनिया भर का समर्थन मिलता है और 15 देशों में क्रांति हो जाती है, तिब्बत में आत्मदाह की खत्म न होने वाले सिलसिले पर भी किसी तरह की प्रतिक्रिया न होना या संयुक्त राष्ट्र और सरकारों द्वारा किसी तरह का कदम न उठाने से इस बात का संदेह पैदा होता है कि दुनिया की वास्तविक सहानुभूति असल में मानवीय एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्धता के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए मिलती है।

वे प्रमुखता से ऐसा सोचना शुरू कर सकते हैं कि वैश्विक समुदाय ऐसे चरण में पहुंच गया है जहां वैश्विक जनमत समूचे विश्व के सामूहिक नैतिक ताकत से ज्यादा एक देश के आर्थिक ताकत से प्रभावित होती है। इन सबसे भी ज्यादा जामफेल येशी ने वैश्विक समुदाय के सामने एक सवाल छोड़ दिया हैः क्या हम ऐसी हालत में पहुंच चुके हैं जहां दुनिया भर के हजारों संघर्षरत समुदाय संघर्षों के समाधान के लिए वैध साधन के रूप में लोकतांत्रिक और अहिंसक अभिव्यक्ति की प्रभावोत्पादकता पर भरोसा छोड़ दें।

तिब्बतियों का आत्मदाह इतिहास में आग से आत्महत्या की सबसे बड़ी लहर है

(एपी, 2 अप्रैल, बीजिंग)

चीनी शासन के विरोध में पिछले सालों में कई दर्जन तिब्बती आत्मदाह कर चुके हैं। कई बार वे अपने शरीर को तेज लपटों में जलाने के लिए केरोसीन पी जाते हैं। यह हाल के इतिहास में राजनीतिक आत्मदाह की सबसे बड़ी लहर है। लेकिन बाहरी दुनिया में इन चरम विरोध प्रदर्शनों पर बहुत गौर नहीं किया जा रहा। इसकी वजह यह है कि चीन के सुरक्षा बलों ने इस इलाके में सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं और किसी भी बाहरी पत्रकार को इस इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा है। जबकि दिसंबर, 2010 में ट्यूनीशिया में सिर्फ एक सब्जी विक्रेता के आत्मदाह ने समूची अरब दुनिया में स्प्रिंग लोकतांत्रिक आंदोलन की आग भड़का दी थी। अभी तक तिब्बती आत्मदाह से विरोध प्रदर्शन करने वालों की मांग के अनुरूप कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। उनकी मांग तिब्बती इलाके में सरकारी हस्तक्षेप खत्म करने और परमपावन दलाई लामा को वापस बुलाने की है। विशेषज्ञों के अनुसार आत्मदाह ऐतिहासिक रूप से विरोध का एक ताकतवर तरीका रहा है और तिब्बत में शुरू हुआ यह सिलसिला व्यापक जनक्रांति को जन्म दे सकता है या चीन पर ज्यादा अंतरराष्ट्रीय दबाव बना सकता है। तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी चीन के बाजारों में मुख्य चौराहों पर, सैन्य शिविरों में और सरकारी प्रशासन के प्रतीक अन्य जगहों पर खुद को आग लगाई है और ज्यादातर ऐसी घटनाएं एक ही आंतरिक काउंटी में हुई हैं। इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर लोग बौद्ध भिक्षु समुदाय से जुड़े रहे हैं। हाल की ऐसी दो नवीनतम घटनाओं में शुक्रवार को 21 और 22 साल के दो भिक्षुओं ने आत्मदाह किए हैं। राजनीति प्रेरित आत्महत्याओं पर अध्ययन करने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के समाजशास्त्री माइकल बिग्स ने कहा, "पैमाने के हिसाब से यह पिछले छह दशकों में आत्मदाह की सबसे बड़ी लहर है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह चीन के एक छोटे क्षेत्र में और एक छोटे नस्लीय समूह में हो रही हैं, जनसंख्या की तुलना में तीव्रता के लिहाज से यह और बड़ी लहर लगती है।"

जानकारों के अनुसार एक साल से भी कम समय में 32 आत्मदाह का सिलसिला वियतनाम युद्ध के दौरान आत्मदाह और दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र समर्थकों के आत्मदाह के सिलसिले भी तेज है। बिग्स ने कहा कि हालांकि, इसके पहले भारत में 1990 में जाति आधारित आरक्षण के विरोध में 100 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आत्मदाह कर लिया था। बिग्स एवं अन्य जानकारों का कहना है कि ज्यादातर लोगों की संवदेना को झकझोरने वाले ये आत्मदाह सुनियोजित, अतिसाहसिक और ताकतवर साबित होते हैं। इसका प्रभाव काफी दूर तक

हान बहुसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग सरकार के इस नजरिए का समर्थन करते हैं कि तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारी तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं। हालांकि, तिब्बती क्षेत्रों में इन आत्मदाहों के बाद अक्सर व्यापक विरोध प्रदर्शन होते हैं

होता है, ऐसे लोगों में भी सहानुभूति पैदा हो जाती है जो आंदोलन से नहीं जुड़े होते हैं और यह समान विचार वाले लोगों को कुछ करने के लिए प्रेरित कर जाते हैं। बौद्धों के लिए (जो कि ज्यादातर तिब्बती हैं) शरीर को जलाना एक निस्वार्थ बलिदान माना जाता है, खासकर धर्म की रक्षा के लिए और इसकी इतिहास में गूंज सुनाई देती है। बौद्धों के आत्मदाह के बारे में लिखी पुस्तक ''बर्निंग फॉर द बुद्ध'' के लेखक जेम्स बेन ने बताया कि छठी शताब्दी में चीनी भिक्षु दाझी ने जलने के लिए एक गर्म जलते हुए लोहे और चाकू का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पहले एक बांह से मांस निकाला, फिर हड्डियां निकाली और विरोध में उनको आग के हवाले कर दिया। दाझी चीन के सुई वंश के एक शासक द्वारा बौद्ध समुदायों पर लगाए कुछ प्रतिबंधों का विरोध कर रहे थे। कई बार राजनीतिक विरोध एवं आत्महत्या के बीच अंतर बहुत धुंधला होता है। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में औरतों के बीच आत्महत्या के लिए आत्मदाह बहुत आम तरीका है। ट्यूनिशिया में फल विक्रेता मोहम्मद बुआजीजी के आत्मदाह के बाद आत्मदाह की अन्य कई घटनाएं हुईं, लेकिन जानकारों का कहना है कि उनमें से ज्यादातर घटनाएं व्यक्तिगत वजहों से हुई आत्महत्याएं हो सकती हैं न कि विरोध प्रदर्शन के लिए हुई आत्महत्या।

विरोध के लिए आधुनिक युक्ति के रूप में आग से आत्महत्या करने का प्रभावी इस्तेमाल वियतनामी बौद्ध भिक्षु थिच क्वांग डुक ने किया, जब 1963 में वे व्यस्त साइगॉन चौराहे पर कमल आसन में बैठ गए और उनके ऊपर दूसरे भिक्षुओं ने पेट्रोल गिराया और माचिस से आग लगा दी। इसे दिखाने के लिए पत्रकारों को भी पहले ही बुला लिया गया था। यह बौद्ध भिक्षु दक्षिण वियतनाम सरकार द्वारा बौद्धों के खिलाफ भेदभाव का विरोध कर रहे थे। उनके इस कृत्य से अमेरिका में युद्ध विरोधी माहौल बनना शुरू हो गया और अमेरिकी सहयोग से बनी सरकार को समर्थन कम होता गया। इसके बाद अहिंसक सामाजिक बदलावों पर लिखी एक पुस्तक में वियतनाम के भिक्षु थिच न्हात हान्ह ने डुक के आत्मदाह के बारे में लिखा, "जब कोई व्यक्ति हिंसा के खिलाफ ऐसे साहसी तरीके से खड़ा होता है तो बदलाव के लिए ताकत निकल पड़ती है। सबसे दर्दनाक तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दुनिया भर के लोगों के हृदय में आग लगा दी।" अभी तक तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारी वह पाने में विफल रहे हैं जो वे चाहते हैं। हर आत्मदाह के बाद प्रशासन ने उस इलाके में सुरक्षा बंदोबस्त और चुस्त कर दिया है जो साल 2008 में चीनी शासन के खिलाफ हुए जनक्रांति के बाद से ही बाहरी दुनिया के लिए बंद रखा गया है। सुरक्षा घेरे ने इस इलाके से पत्रकारों को बाहर ही रखा है। तिब्बतियों की तलाशी लगातार ली जा रही है और इंटरनेट एवं मोबाइल सेवा पर लगने वाले रोक की वजह से बाहर कोई भी जानकारी प्रसारित नहीं हो पाती। आत्मदाह करने वाले व्यक्तियों की तस्वीरें बाहर न आ पाने की वजह से इन आत्मदाहों का बाहरी दुनिया पर असर कम हो रहा है। इसके साथ ही बात यह भी है कि चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके बढ़ते राजनयिक प्रभाव से इस बात की संभावना कम होती जा रही है कि विदेशी सरकारें तिब्बती मसले को वजन दें। बिग्स ने कहा, "वास्तव में यह बात मानी जाती है कि थिच क्वांग डुक और अन्य बौद्ध भिक्षुओं के साल 1963 में साइगॉन में आत्मदाह से अमेरिकी विदेशी नीति में बदलाव करना पड़ा था और इससे दक्षिणी वियतनाम की सरकार गिर गई थी। लेकिन निश्चित रूप से चीन पर इतना असर नहीं हो सकता।" यह विरोध प्रदर्शनकारी चीनी जनसंख्या को झकझोरने में सफल नहीं हो पाए हैं जो कि इस युक्ति को उसी तरह समझ रही है जब साल 2001 में टिनामेन चौक पर प्रतिबंधित फालुन गोंग आध्यात्मिक आंदोलन के पांच सदस्यों ने खुद को आग लगा लिया था। उक्त घटना में एक महिला और उसकी एक 12 साल की लड़की का भी निधन हो गया था। चीन ने इस घटना का इस्तेमाल अपना यह दावा मजबूत करने में किया था कि फालुन गोंग 'एक शैतानी पंथ' है और उसने इसके नाते ही अपने बर्बर दमन को भी न्यायोचित ठहराया था। चीनी जनता को तिब्बतियों की अपील पर बहुत कम सहानुभूति है। हान बहुसंख्यक समुदाय के बहुत से लोग सरकार के इस नजरिए का समर्थन करते हैं कि तिब्बती विरोध प्रदर्शनकारी तिब्बत को चीन से अलग करना चाहते हैं। हालांकि, तिब्बती क्षेत्रों में इन आत्मदाहों के बाद अक्सर व्यापक विरोध प्रदर्शन होते हैं जो इस बात को रेखांकित करते हैं कि तिब्बती समुदाय को जगाने के लिए यह विरोध कितने मजबूत उपाय साबित हो रहे हैं।

जनवरी माह में क्विंघई प्रांत में सोपा नाम के 42 साल के एक भिक्षु ने केरोसीन पी लिया और उसे अपने शरीर पर भी उड़ेल लिया और इसके बाद उन्होंने खुद को आग लगा ली। रेडियो फ्री एशिया ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि पुलिस द्वारा शव को अपने साथ ले जाने से पहले उनका शरीर विस्फोट होकर कई टुकड़ों में बंट गया था। खबरों के अनुसार इसके बाद स्थानीय लोगों ने भिक्षु का शव उन्हें सौंपने की मांग को लेकर स्थानीय पुलिस थाने की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए और इसके बाद विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन भी किया।

पेनसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में आतंकवाद विशेषज्ञ जॉन हॉर्गन ने बताया, "आत्मदाह एक असामान्य रूप से प्रभावी मनोवैज्ञानिक युक्ति साबित हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आत्मदाह से निर्दोष प्रत्यक्षदर्शियों की मौत नहीं होती, इसे अक्सर अत्यंत श्रेष्ठ भाव माना जाता है जो कुंठा और असहायता से उपजता है।" हॉर्गन दुनिया भर में आत्मदाह पर डेटाबेस तैयार करने की एक परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉर्गन ने कहा कि आत्मदाह का वैसा नकारात्मक संबंध नहीं होता जैसा कि आत्मघाती बम विस्फोट का होता है, लेकिन इसे भी उसी तरह का प्रचार मिलता है। दक्षिण कोरिया में साल 1971 से 1993 के बीच हुए आत्मदाहों पर पेनसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ बेन पार्क ने कहा, "जब वास्तव में व्यापक रूप से कुंठा पनप जाती है और सभी विकल्पों का कोई असर नहीं होता तब विरोध प्रदर्शन के लिए आत्मदाह की युक्ति को गंभीरता से लिया जाता है।" पार्क ने बताया कि पिछले दो दशकों में कोरिया में अधिनायकवादी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए करीब 70 लोगों ने आत्मदाह कर लिया है जिसमें से ज्यादातर शहरों में बसने वाले युवा ग्रामीण प्रवासी हैं।"